relating to resettlement of displaced persons examined by another group of experts including those nominated by Shri Bahuguna.

Construction activities at the Project site are continuing and the coffer dam has been raised to a height of EL 660 metres.

Barren land Reclamation Programme

1248. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT to be pleased to state:

(a) whether Government are implementing Barren Land Reclamation Programme;

(b) if so, the total acreage of land made cultivable under this programme during the last three years. State-wise;

(c) whether any Barren Land Development Schemes from States are pending with the Central Government for approval; and

(d) if so, the details thereof. State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERM A): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता से जल आपूर्ति

1249. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक एवं अन्य विदेशी संस्थाओं की वित्तीय सहायता से विभिन्न जिलों में जल की आपूर्ति में सुधार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के बारे में विश्व बैंक एवं अन्य संस्थाओं से विचार-विमर्श करने का विचार रखती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) अन्य प्रदेशों में ऐसी वित्तीय सहायता से पेयजल आपूर्ति के लिए जो परियोजनाएं स्वीकृत होकर कार्यान्वित की जा रही हैं, उनका ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) (I) 51.7 करोड़ रूपये की लागत से भोपाल शहर की जल आपूर्ति क्षमता बढ़ा कर 594 मिलियन लीटर दैनिक करने तथा विद्यमान वितरण प्रणाली के विस्तार का कार्यक्रम है।

(II) 46 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से स्थापित क्षमता बढ़ाने और मौजूदा वितरण प्रणाली के विस्तार हेतु जबलपुर जल आपूर्ति परियोजना।

(III) 105 छोटे व मझौले कस्बों के लिए पेय जल आपूर्ति परियोजना, ताकि 400 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से आपूर्ति स्तर, रिसाव ज्ञात कर उसकी रोकथाम, जल गुणवत्ता की निगरानी और भू-जल शोधन।

(ग) और (घ) भोपाल और जबलपुर की जल आपूर्ति परियोजनाएं जर्मन सहायता के लिए भेजी गयी थीं लेकिन उनका अंतिम अनुमोदन नहीं हुआ है। राज्य सरकार से 105 छोटे व मझौले कस्बों बाबत साध्यता-पूर्व रिपोर्ट मंगायी है ताकि विदेशी मद्द हेतु पेश करने से पूर्व उसकी जांच की जा सकें।

(ङ) अन्य राज्यों में विदेशी सहायता से चल रही पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विदेशी सहायता से अन्य राज्यों में चल रही शहरी पेय जल आपूर्ति परियोजनाओं की सूची

क्रम सं॰	परियोजना (क्षेत्र)	लागत (करोड़ रू॰ में)	विदेशी सहायता (मिलियन में)	स्रोत
1.	हैदराबाद जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना (हैदराबाद व सिकन्दराबाद)	257.06	89.9 अमरीकी डालर	विश्व बैंक
2.	मद्रास जल आपूर्ति न्यू वीरानम (मद्रास)-II	1638.037	275.8 अमरीकी डालर	विश्व बैंक
3.	मद्रास जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली (मद्रास)	323.10	17,098 येन	ओ.ई.सी.एफ. जापान
4.	कावेरी जल आपूर्ति स्कीम स्टेज-II/चरण-I (बंगलौर)	1209.80	28,452 येन	ओ.ई.सी.एफ. जापान